



42 वर्ष के हुए रणवीर...



www.swatantrammat.com

स्वतंत्र मात



नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय...

वर्ष 29 अंक 95

डाक/नगर संस्करण

जबलपुर रविवार 29 सितम्बर 2024

पृष्ठ 12 मूल्य रु. 3.00

30वीं नेशनल कांफ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इंप्लान्टोलॉजिस्ट में बोले मुख्यमंत्री

इंदौर।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे आयुष्मान योजना के तहत दांत के इलाज की सिफारिश करेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ऊपर के लोगों को भी इलाज की सुविधा दी है। इतना ही नहीं आयुष्मान कार्डधारी को एयर एम्बुलेंस

आयुष्मान योजना के तहत दांत के इलाज की सिफारिश करेंगे

की सुविधा भी दी जा रही है। सीएम शनिवार को ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में 30वीं नेशनल कांफ्रेंस ऑफ इंडियन सोसायटी ऑफ ओरल इंप्लान्टोलॉजिस्ट का शुभारंभ करने आए थे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर क्षेत्र में नवाचार किए और ऐसे कामों को प्रोत्साहन दिया है। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन दो मंत्रालय थे। मैंने सबसे पहले दोनों को एक किया, ताकि हेल्थ की सुविधा भी अच्छी



मिले और एजुकेशन व्यवस्था भी ठीक रहे।

चिकित्सा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पर 40 फीसदी सलिसडी

सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने पर सरकार की तरफ से 40 फीसदी तक की सलिसडी दी जा रही है। मध्यप्रदेश देश का दिल है, आप दिल के करीब आएं। सरकार जमीन से लेकर हर तरह की मदद आपको करेगी।

दांत तोड़ने की बात सब करते हैं

सीएम ने कहा कि यहां दांत तोड़ने की बात तो सब करते हैं, लगाने वाले कम मिलते हैं। आपको दुनिया बहुत अलग है। पहले नकली दांत लगाते थे, जिसे साफ करना पड़ता है। अब तो इंप्लांट करा लो और भूल जाओ। निकालने और साफ करने का इंडेंट नहीं। कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक मालिनी गौड़, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित कई नेता व दांत चिकित्सक मौजूद थे।

बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश

इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप

बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुये अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस



स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। इधर, इस खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सिद्धारमैया ने कहा है कि, कर्नाटक भाजपा के नेता सीतारमण के इस्तीफे के लिए कब प्रदर्शन और मार्च करेंगे। अगर निष्पक्ष जांच होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी और कुमारस्वामी को भी इस्तीफा देना चाहिए।

26 नवंबर से पहले होंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी जानकारी

मुंबई।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद है। राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू दो दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना, शिवसेना यूबीटी, मनसे, बसपा, आप समेत 11 पार्टियों से मुलाकात की। सभी पार्टियों ने



मांग की है कि दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमने महाराष्ट्र सरकार से उन अधिकारियों का तबादला करने का अनुरोध किया है, जो अपने गृह जिले या मौजूदा पोस्टिंग में 3 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं। यह चोटर्स का अधिकार है कि उन्हें पता हो किस कैडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। पार्टियों को अपने कैडिडेट के बारे में ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

शिकायत में जेपी नड्डा का भी नाम

जनाधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल में 42वीं एसीएमएम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटौल, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरविंदो फार्मसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए।

यह है पूरा मामला
इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि

सुको ने कहा था- स्क्रीम असंवैधानिक

15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्क्रीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- यह स्क्रीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्क्रीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने एसबीआई और चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा सार्वजनिक करे।

वित्त मंत्री ने कहा था- स्क्रीम वापस लाएं

लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने बॉन्ड स्क्रीम को दोबारा लाने का संकेत दिया था। निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्क्रीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके इस बयान पर कहा था- अब बीजेपी लोगों को और कितना लूटना चाहती है।

इच्छामृत्यु को लेकर गाइडलाइन जारी

आईएमए के अध्यक्ष बोले- इससे तनाव में आएंगे डॉक्टर



नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानी गंभीर रूप से बीमार मरीजों को लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर बेहद सोच-समझकर ये फैसला लेना होगा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाना जाना चाहिए या नहीं। गाइडलाइन्स में चार शर्तें तय की गई हैं, जिनके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि लाइफ सपोर्ट को रोकना मरीज के हित में उचित है। यह तब किया जाएगा जब यह साफ हो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज को लाइफ सपोर्ट से कोई फायदा होने की संभावना नहीं है, या लाइफ सपोर्ट पर रखने से मरीज की तकलीफ बढ़ने और गरिमा को नुकसान पहुंचाने की संभावना हो। सरकार की इन गाइडलाइन्स को लेकर मेडिकल फ्रेटरनिटी में असंतोष देखा जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉ. आर.वी. असोकन ने कहा कि ये दिशा-निर्देश डॉक्टरों को कानूनी जांच के दायरे में लाएंगे और उन पर तनाव डालेंगे।

जम्मू-कश्मीर में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी: मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा- अब कोई भी देश के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करेगा

जम्मू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सितंबर 2016 में हुई सर्विकल स्ट्राइक ने भारत के दुश्मनों को हिलाकर रख दिया है और अब कोई भी देश के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद के आकाओं को पता है कि मोदी उन्हें कहीं भी छुपकर ढूंढ निकालेंगे। प्रधानमंत्री ने जम्मू में विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनकी आखिरी चुनावी रैली है, क्योंकि एक अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा आज 28 सितंबर है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक सर्विकल स्ट्राइक की सालगिरह। इसी दिन हमने दुश्मनों को उनके घरों में घुसकर मारा और दुनिया को दिखाया कि



यह नया भारत है, जिसे अब और हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि 2016 की सर्विकल स्ट्राइक ने आतंकवाद के आकाओं को सबसे बड़ा सबक सिखाया है क्योंकि अब कोई भी भारत की संप्रभुता को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा 2016 के सर्विकल स्ट्राइक ने आतंकवाद के समर्थकों को सबक सिखाया है कि भारत की संप्रभुता को छूने

की हिम्मत कोई नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भारत के खिलाफ कोई हरकत करता है, तो मोदी सरकार उन्हें कहीं भी छुप जाने की जगह नहीं देगी और उन्हें सबक सिखाएगी।

भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि

उन्होंने पूछा क्या वे वोट के लायक हैं? उन्होंने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती थी है। उन्होंने कहा आज में इस शहीद नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों को यात्रा की। उन्होंने कहा मैं जहां भी गया, मैंने लोगों में भाजपा के प्रति बहुत उत्साह देखा। जम्मू-कश्मीर के लोग कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस से थक चुके हैं।

मणिपुर में फिर हिंसा: मैतेई गांव में अंधाधुंध फायरिंग

इंफाल। मणिपुर के जिरिबाम जिले में शनिवार 28 सितंबर को फिर हिंसा हुई। पुलिस ने बताया कि संधिभंग उपद्रवियों ने सुबह करीब 11:30 बजे मोंगबुंग मैतेई गांव में अंधाधुंध फायरिंग की। गांव के वालंटियर ने जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल गोलीबारी जारी है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ चुरचुरादपुर और कांगपोकपी जिलों में आज बंद का दूसरा दिन है। इसके कारण बाजार बंद रहे। सड़कें बंद कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि कुकी-जो समूहों ने दोनों जिलों में आज रविवार 29 सितंबर तक बंद का आह्वान किया है। इंडियनस ट्राइबल लीडर्स फोरम और कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन सहित अन्य कुकी समुदाय सिक्किम और कुकी एडवाइजर कुलदीप सिंह के बयान का विरोध कर रहे हैं। कुलदीप सिंह ने 20 सितंबर को दावा किया था कि मणिपुर में ग्यांगार से 900 कुकी उग्रवादी घुस गए हैं। पुलिस ने कांगपोकपी जिले के लोईचिंग रिज से दो 303 राइफल, मैगजीन के साथ एक 9 मिमी पिस्तौल, कारतूस, चार हैंड ग्रेनेड, दो डेटोनैटर और एक देसी मोटार और लंबी दूरी का इम्प्रोवाइज्ड मोटार ज्वट किया है।



दिव्यांग बच्चों की परेशानियां समझे न्याय व्यवस्था : सीजेआई



नई दिल्ली।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि न्याय व्यवस्था को दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को समझना चाहिए। मेरी दो दिव्यांग बेटियां हैं, जिन्होंने मेरा दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया है। सीजेआई बाल संरक्षण पर नौवें नेशनल एनुअल स्ट्रेकहोल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। सीजेआई, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और जस्टिस नागरला ने दिव्यांग व्यक्तियों पर हेंडबुक जारी की। यह समाज को सही

शब्दावली का इस्तेमाल करने में मदद करेगी। सीजेआई ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में पुलिस से लेकर कोर्ट तक दिव्यांग बच्चों की परेशानियों को समझना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शारीरिक चुनौतियों के साथ-साथ समाज में मौजूद गलत धारणाओं का भी सामना करना पड़ता है। दिव्यांग लिंग, जाति और आर्थिक स्थिति के साथ मिलकर और भी अधिक भेदभाव पैदा करती है। उन्होंने जूडिशियल सिस्टम में पुनर्संस्थापनात्मक न्याय (रेस्टोरेटिव जस्टिस) के तरीकों को शामिल करने पर जोर दिया, जिससे बच्चों को शिक्षा और चोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके। समानता, सम्मान और भेदभाव न होना दिव्यांग बच्चों के मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि ऐसे दिव्यांग बच्चों का कोई डटा नहीं जो सेक्सुअल ऑफेंस से पीड़ित होते हैं या कानून के साथ कैसे भी टकराते हैं। ऐसे दिव्यांग बच्चों के मुद्दों के दायरे को समझे बिना नीतियां कैसे बना सकते हैं और समाधान कैसे लागू कर सकते हैं? इस पर उन्होंने सुझाव दिया कि हमें जुवेनाइल जस्टिस के फ्रेमवर्क में डेटा कलेक्शन सिस्टम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

केंद्र की नीतियों ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- युवा विरोधी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवा विरोधी हैं और उनकी नीतियों ने युवाओं के लिए रोजगार के कोई अवसर पैदा नहीं किए हैं, जिससे देश का युवा बर्बाद हो गया है। खड़गे ने कहा बेरोजगारी से बड़ा देश में कोई मुद्दा नहीं है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। अभी आए पीएलएफएस के आँकड़ों को अगर बारीकी से देखें तो लाख कोशिशों के बावजूद ये सरकारी डेटा युवाओं की बेबसी को छिपा नहीं पा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया और कहा, नरेन्द्र मोदी को



नहीं है कि जिन महिलाओं के पास रेगुलर आय की नौकरी है उनकी संख्या अब सात वर्षों में सबसे कम होकर मात्र 15.9 प्रतिशत रह गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा क्या गाँव-देहात में अनपेड नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या 2017-18 के 51.9 प्रतिशत से बढ़कर अब 67.4 प्रतिशत नहीं हुई है, जो ग्रामीण बेरोजगारी को दर्शाता है। विनिर्माण क्षेत्र पर रोज़ाना ढिंढोरा पीटने वाली

बताना चाहिए क्या 2023-24 में युवा बेरोजगारी 10.2 प्रतिशत के भयावह स्तर पर नहीं है। रंग-बिरंगे नारे देने और फोटोबाजी करने के बजाय प्रधानमंत्री ने युवाओं को नौकरियां देने के लिए क्या किया। क्या ये सच है, जिससे देश का युवा बर्बाद हो गया है।

मोदी सरकार ने इसमें पिछले सात वर्षों में आंकड़ा 2017-18 के 15.85 प्रतिशत से रोजगार में बढ़ोतरी क्यों नहीं की है। ये लुढ़ककर अब 11.4 प्रतिशत कैसे रह गया।

भाजपा ने हरियाणा का आत्मसम्मान तक छीन लिया : राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर शनिवार को जमकर हमला करते हुए कहा कि उसने पिछले एक दशक के दौरान हरियाणा की समृद्धि को ध्वस्त करके उसे बर्बाद कर दिया है। राहुल ने एक्स पर कहा भाजपा ने एक दशक में हरियाणा से उसकी समृद्धि, उसके सपने और शक्ति छीन ली। अग्निवीर से देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली, बेरोजगारी से परिवारों की हंसी छीन ली और महंगाई से महिलाओं की आत्मनिर्भरता। काले कानून लाकर किसानों का हक तक छीन लेने का प्रयास किया तो नोडबंदी और गलत फायदे से लाखों छोटे व्यापारियों का मुनाफा छीन लिया। उन्होंने कहा अपने मित्रों को जायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा का आत्मसम्मान तक छीन लिया। कांग्रेस की आने वाली सरकार दद के दशक का अंत करेगी।



